



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102026-276933
CG-DL-E-08102026-276933

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948

No. 308]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026

सेतु मामला आईडी - AD/SSR/011/2026

विषय: चीन पीआर, जापान और कोरिया आरपी में उद्भूत या निर्यात किए गए टोल्यानि डाई-आइसोसाइनेट (टीडीआई) के आयात से संबंधित सूर्यास्त समीक्षा पाटनरोधीजांच की शुरुआत।

1. **फा. सं. 7/24/2026-डीजीटीआर.**— सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, समय-समय पर यथा संशोधित (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 के संबंध में, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित), गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक और रसायन लिमिटेड (इसके बाद 'आवेदक' या 'घरेलू उद्योग' के रूप में संदर्भित) ने एक आवेदन दायर किया है नामित प्राधिकारी (इसके बाद 'प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित) के सामने, टोल्यानि डी-आइसोसाइनेट (टीडीआई) (इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद', 'पीयूसी' या 'विषय सामान' के रूप में संदर्भित) के आयात पर पाटनरोधीशुल्क की सूर्यास्त समीक्षा जांच शुरू करने के लिए, चीन पीआर, जापान और कोरिया आरपी (इसके बाद 'विषय देशों' के रूप में संदर्भित) में उत्पन्न या निर्यात किया गया।

8. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और विषय देशों से निर्यात किए गए उत्पाद के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। दोनों तकनीकी विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं; वे तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। मूल जांच में प्राधिकरण द्वारा समान लेख के मद्दे की भी जांच की गई थी।

तदनुसार, वर्तमान सूर्यास्त समीक्षा के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद को विषय देशों में उत्पादित और आयातित उत्पाद के लिए 'समान वस्तु' के रूप में माना जाता है।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

9. आवेदन गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में विषय वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने विषय देशों से विषय वस्तुओं का आयात नहीं किया है और यह विषय देशों में विषय वस्तुओं के किसी भी उत्पादक या निर्यातक या भारत में विषय वस्तुओं के किसी भी आयातक से संबंधित नहीं है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकरण संतुष्ट है कि आवेदक नियमों के नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का गठन करता है और यह आवेदन 'घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से' किया गया है। आवेदन नियम 5(3) के संदर्भ में खड़े होने की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, भले ही नियम 5(3) की आवश्यकताएं सूर्यास्त समीक्षा जांच पर लागू नहीं होती हैं।

ड. संबद्ध देश

10. वर्तमान जांच में विषय देश चीन पीआर, जापान और कोरिया आरपी हैं, जो मूल जांच और पहली सूर्यास्त समीक्षा जांच में विषय देशों के समान हैं।

च. जांच की अवधि

11. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 महीने) तक है। क्षति परीक्षा की अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 और जांच की अवधि को कवर करती है।

छ. कथित पाटन का आधार

i. चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने दावा किया है कि चीन पीआर को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीनी उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि नियमों के अनुलग्नक-1 के पैरा 8 (3) के संदर्भ में विषय वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल होती है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि वह एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि भारत सहित अन्य देशों के लिए तीसरे देश से बाजार अर्थव्यवस्था की कीमत को अपनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि यूरोपीय संघ और सऊदी अरब से आयात को प्राधिकरण द्वारा उन देशों के संबंध में हाल ही में संपन्न सूर्यास्त समीक्षा जांच में डंप की गई कीमतों पर पाया गया है। इसलिए, आवेदक ने नियमों के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 के संदर्भ में भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, भारत में उत्पादन की लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित किया गया है। शुरुआत के प्रयोजन के लिए, चीन पीआर को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना गया है, जो नियमों के अनुलग्नक-1 के पैरा 8 के अनुसार संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा खंडन के अधीन है, और सामान्य मूल्य का निर्माण नियमों के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है।

ii. जापान और कोरिया आरपी के लिए सामान्य मूल्य

13. प्राधिकरण नोट करता है कि अधिनियम की धारा 9 ए (1) (सी) निर्यात करने वाले देश में खपत के लिए समान वस्तु के लिए व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में तुलनीय मूल्य निर्दिष्ट करती है और, जहां ऐसी कीमत उपलब्ध नहीं है, निर्यातक देश से एक उपयुक्त तीसरे देश में निर्यात किए जाने पर समान वस्तु का एक तुलनीय प्रतिनिधि मूल्य या प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत और मुनाफे के लिए उचित परिवर्धन के साथ मूल देश में उत्पादन की लागत। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि वह जापान और कोरिया आरपी में विषय वस्तुओं के घरेलू बिक्री मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ था। तदनुसार, आवेदक ने सामान्य मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से केमएनालिस्ट वेबसाइट पर प्रकाशित मूल्य जानकारी पर भरोसा किया है। उक्त वेबसाइट एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रचलित विषय वस्तुओं की कीमतों की रिपोर्ट करती है। आवेदक ने संबंधित मूल देशों में विषय वस्तुओं के उत्पादन की लागत का अनुमान प्रस्तुत करके उक्त जानकारी को भी पूरक किया है।

14. प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक द्वारा प्रदान की गई केमएनालिस्ट मूल्य जानकारी जांच की अवधि का केवल एक चौथाई हिस्सा कवर करती है और यह स्पष्ट नहीं करती है कि ऐसी कीमतें देश में खपत की कीमतें हैं या नहीं। उत्पादन की अनुमानित लागत के संबंध में, आवेदक ने इस स्तर पर सत्यापन योग्य अंतरराष्ट्रीय कच्चे माल या उपयोगिता मूल्य प्रदान नहीं किए हैं। जहां तक किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात किए जाने पर समान वस्तु के तुलनीय प्रतिनिधि मूल्य का संबंध है, उस उद्देश्य के लिए उपलब्ध प्रकाशित स्रोत छह अंकों के स्तर पर व्यापार की रिपोर्ट करता है जो केवल विषय वस्तुओं को कवर नहीं करता है। तदनुसार, इस स्तर पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इनमें से किसी पर भी विचार नहीं किया गया है। दीक्षा के उद्देश्य से, जापान और कोरिया आरपी के संबंध में सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों पर निर्धारित किया गया है, भारत में इस तरह की वस्तु के उत्पादन की अनुकूलित लागत को उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के रूप में अपनाया गया है, विधिवत समायोजित किया गया है और उचित लाभ मार्जिन को जोड़ा गया है। शुरुआत के बाद, सामान्य मूल्य संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों की प्रतिक्रियाओं और ऐसे आगे के साक्ष्यों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा जिन्हें रिकॉर्ड पर रखा जा सकता है।

iii. निर्यात मूल्य

15. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात मूल्य विचाराधीन उत्पाद के सीआईएफ मूल्य पर विचार करके निर्धारित किया गया है, जैसा कि डीजी सिस्टम्स लेनदेन वार आयात डेटा में रिपोर्ट किया गया है। आवेदक द्वारा किए गए दावे के अनुसार उचित समायोजन पर समुद्री माल दुलाई, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, इन्वेंट्री ले जाने की लागत और ऋण लागत के कारण एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य पर पहुंचने पर विचार किया गया है।

iv. डंपिंग मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और ऊपर बताए गए अनुसार निर्धारित निर्यात मूल्य के आधार पर, डंपिंग माजन क्या है? प्रथम दृष्टया प्रत्येक विषय देश के लिए सकारात्मक और महत्वपूर्ण, प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि विषय देशों से विषय वस्तुओं की डंपिंग जारी है।

ज. पाटन और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना

17. आवेदक ने प्रदान किया है प्रथम दृष्टया घरेलू उद्योग को लगातार नुकसान का साक्ष्य। भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में विषय देशों से आयात की मात्रा में पूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। संबंधित देशों से कीमत में कटौती सकारात्मक है, डंप किए गए आयात ने प्रथम दृष्टया आवेदक की कीमतों को कम कर दिया है, जो क्षति की अवधि के दौरान बिक्री की लागत से कम हो गया है, और विषय आयात का लैंडेड मूल्य घरेलू उद्योग के गैर-हानिकारक मूल्य से कम है। आवेदक ने इष्टतम क्षमता उपयोग से कम काम किया है, क्षति की अवधि में इसकी बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, और इसे वित्तीय नुकसान, नकद हानि और क्षति की अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न का सामना करना पड़ा है। आवेदक ने आगे दावा किया है कि पाटनरोधीशुल्क की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना है, क्योंकि संबंधित देशों में उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमता है, जो भारत में मांग से कई गुना अधिक है, और चीन पीआर में और क्षमता विस्तार किया जा रहा है। इसने यह भी दावा किया है कि संबंधित देशों में उत्पादक निर्यातोन्मुखी हैं, और यह कि संबंधित देशों से तीसरे देशों को निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा घरेलू उद्योग के अनुमानित सामान्य मूल्य और गैर-हानिकारक मूल्य से कम कीमतों पर है, और भारत को निर्यात मूल्य से कम है। आवेदक द्वारा दी गई जानकारी प्रथम दृष्टया (ख) सरकार ने संबंधित देशों से पाटन की निरंतरता और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में डंपिंग के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने की संभावना को दर्शाया है।

झ. सूर्यास्त समीक्षा जांच की शुरुआत

18. आवेदक द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर, और इसके आधार पर खुद को संतुष्ट करने के बाद, प्रथम दृष्टया आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य डंपिंग और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना की पुष्टि करते हैं, और नियमों के नियम 23(1बी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 ए (5) के अनुसार, प्राधिकरण एतद्वारा विषय देशों में उत्पन्न होने वाली या निर्यात की जाने वाली विषय वस्तुओं के संबंध में लागू पाटनरोधीशुल्क के निरंतर अधिरोपन की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए एक सूर्यास्त समीक्षा जांच शुरू करता है, और यह जांचने के लिए कि क्या इस तरह के शुल्क की समाप्ति से डंपिंग की निरंतरता या पुनरावृत्ति होने की संभावना है और घरेलू उद्योग को क्षति लगने की संभावना है।

ज. प्रक्रिया

19. सूर्यास्त समीक्षा जांच में अंतिम निष्कर्ष संख्या 14/36/2016-डीजीएडी दिनांक 13 दिसंबर 2017 के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें संबंधित देशों में उत्पन्न होने वाली या उनसे निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधीशुल्क लगाने की सिफारिश की गई है और अंतिम निष्कर्ष संख्या 7/26/2021-डीजीटीआर दिनांक 27 अगस्त 2021 ने पाटनरोधीशुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है।
20. नियमों के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में विभिन्न परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

ट. जानकारी प्रस्तुत करना

21. सभी इच्छुक पार्टियों को सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है। इच्छुक पार्टियों के सभी संचार और सबमिशन उनके पंजीकृत नाम और संबंधित सेतु केस आईडी - एडी/एसएसआर/011/2026 के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सबमिशन का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।
22. संबंधित देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से संबंधित देशों की सरकारों और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को इस विषय के सामान से संबंधित होने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे दी गई समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस दीक्षा अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से दर्ज की जानी चाहिए।
23. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी वर्तमान जांच के लिए फॉर्म और तरीके से प्रासंगिक सबमिशन कर सकता है, और समय सीमा के भीतर, इस अधिसूचना में निर्धारित नियम, और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिस। प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय सबमिशन करने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पार्टियों को उसी का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।
24. इच्छुक पार्टियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित रूप से नजर रखें। इच्छुक पार्टियों को निर्देश दिया जाता है कि वे नियमित रूप से डीजीटीआर (<http://dgtr.gov.in/>) की वेबसाइट पर जाएं ताकि वे विषय की जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहें और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य जानकारी के संबंध में समय-समय पर जारी किए जा सकने वाले नोटिसों के बारे में सूचित रहें।

ठ. अंतिम तिथि

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी इच्छुक पार्टियों द्वारा अपने पंजीकृत नाम और संबंधित सेतु केस आईडी - AD/SSR/011/2026 के तहत SETU पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक सबमिशन के दोनों संस्करण, गोपनीय संस्करण (CV) और गैर-गोपनीय संस्करण (NCV), को सूचना पत्रों के प्रसारण की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का गैर-गोपनीय संस्करण और संबंधित प्रश्नावली शामिल है, जो ज्ञात इच्छुक पार्टियों और विषय देशों के राजनयिक प्रतिनिधि (ओं) को पाटनरोधीनियम, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी है, तो प्राधिकरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमों के अनुसार अपने निष्कर्ष रिकॉर्ड कर सकता है।
26. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दाखिल करें।

27. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणी दर्ज करने के लिए 15 दिन की अवधि इस दीक्षा अधिसूचना के पैराग्राफ 25 में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
28. पीयूसी/पीसीएन के संशोधन के कारण विस्तार: 15 दिनों तक समय का विस्तार दिया जाएगा यदि प्राधिकरण, बाद के नोटिस के माध्यम से, पीयूसी और पीसीएन को संशोधित करता है जो पहले प्रस्तावित नहीं था या दीक्षा अधिसूचना से अलग है। संशोधित पीयूसी और पीसीएन की ऐसी अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में बताए गए 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई बदलाव नहीं होता है। 15 दिनों के विस्तार (यदि दी गई हो) से परे समय के और विस्तार के अनुरोधों पर आमतौर पर नियमों के नियम 6(4) के अनुरूप असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर विचार नहीं किया जाएगा।
29. विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद सबमिट किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना

30. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्ष गोपनीय प्रस्तुतियाँ करता है या प्राधिकरण के समक्ष गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, ऐसे पक्ष को नियमों के नियम 7(2) के संदर्भ में और इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार नोटिसों के अनुसार ऐसी जानकारी का एक गैर-गोपनीय संस्करण एक साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियाँ अस्वीकृत हो सकती हैं।
31. प्रश्नावली के उत्तरों सहित प्राधिकरण के समक्ष कोई भी प्रस्तुतीकरण (परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षों को गोपनीय और गैर-गोपनीय संस्करण अलग-अलग दाखिल करने की आवश्यकता होती है।
32. इस तरह के सबमिशन को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'गैर-गोपनीय' के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के चिह्नों के बिना प्राधिकरण को किए गए किसी भी सबमिशन को प्राधिकरण द्वारा 'गैर-गोपनीय' जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकरण अन्य इच्छुक पार्टियों को इस तरह के सबमिशन का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।
33. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो प्रकृति से, गोपनीय और/या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। उस जानकारी के लिए जो प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या वह जानकारी जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, जानकारी के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।
34. इच्छुक पार्टियों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या खाली कर दी गई हो (जहां इंडेक्सेशन संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी को उस जानकारी के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशित किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।
35. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी के सार की उचित समझ की अनुमति देने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और नियमों के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण वाले कारणों का एक विवरण, और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए उपयुक्त व्यापार नोटिस, कि ऐसा सारांश संभव क्यों नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।
36. इच्छुक पार्टियाँ दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रचलन की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकती हैं।
37. इसके सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण या नियमों के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त कारण विवरण के बिना किया गया कोई भी सबमिशन, और गोपनीयता के दावे पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए उपयुक्त व्यापार नोटिस को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

38. प्राधिकरण प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध की आवश्यकता नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।
39. प्राधिकरण संतुष्ट होने और प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पक्ष को इसका खुलासा नहीं करेगा।
- ढ. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण**
40. किसी भी इच्छुक पार्टी द्वारा किए गए सबमिशन के सभी गैर-गोपनीय संस्करण अन्य इच्छुक पार्टियों के लिए सेटु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।
- ण. असहयोग**
41. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस आरंभिक अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उचित अवधि के भीतर या निर्धारित समय के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है और अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकरण ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो वह उचित समझे।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2026

SETU CASE ID - AD/SSR/011/2026

Subject: Initiation of sunset review anti-dumping investigation concerning imports of Toluene Di-Isocyanate (TDI) originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP.

- F. No. 7/24/2026-DGTR.**— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (hereinafter referred to as the 'applicant' or the 'domestic industry') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), for initiation of a sunset review investigation of the anti-dumping duty on imports of Toluene Di-Isocyanate (TDI) (hereinafter referred to as the 'product under consideration', the 'PUC' or the 'subject goods'), originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP (hereinafter referred to as the 'subject countries').
- In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition. The Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

A. Background of previous investigations

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries was initiated by the Authority on 5th October 2016. The preliminary findings were issued vide Notification No. 14/36/2016-DGAD dated 28th March 2017, recommending imposition of provisional anti-dumping duty, which was imposed by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 25/2017-Customs (ADD) dated 5th June 2017. The Authority issued the final findings dated 13th December 2017, confirming the preliminary findings and recommending imposition of anti-dumping duty, which was imposed by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 3/2018-Customs (ADD) dated 23rd January 2018 for a period of five years.
4. Thereafter, the Authority initiated the first sunset review investigation vide Notification F. No. 7/26/2021-DGTR dated 27th August 2021. The Authority issued the final findings dated 24th June 2022, and recommended continued imposition of anti-dumping duty. The same was accepted and duties were continued by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 28/2022-Customs (ADD) dated 21st September 2022. The said duty is in force till 20th September 2027, unless revoked earlier.

B. Product under consideration

5. The present application being a sunset review investigation, the product under consideration remains the same as defined in the original investigation, which is as follows:

“The product under consideration in the present investigation is ‘Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20’. Toluene di-isocyanate (TDI) is an organic compound having formula $CH_3C_6H_3(NCO)_2$. Two of the six possible isomers are commercially important: 2,4-TDI (CAS: 584-84-9) and 2,6-TDI (CAS: 91-08-7). 2,4-TDI is produced in the pure state, but TDI is often marketed as 80/20 and 65/35 mixtures of the 2,4 and 2,6 isomers respectively. The product under consideration in the present investigation concerns TDI having isomer content in the ratio of (80:20). All other grades are beyond the scope of the product under consideration.

The product is classified under Chapter Heading 29 under the code 2929 10 20. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.”

6. The subject goods are used in the production of flexible polyurethane foam, which finds application in furniture cushions, industrial gaskets, protective pads, automobile seats and linings, and packaging. The unit of measurement considered in the present investigation for the product under consideration is Metric Tonnes (MT).
7. The applicant has not proposed a Product Control Number ("PCN") methodology. All interested parties are advised to furnish their comments on the scope of the PUC and the PCN methodology, if required, within 15 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country/countries.

C. Like article

8. The applicant has claimed that there is no significant difference between the product produced by the domestic industry and that exported from the subject countries. The two are comparable in terms of technical specifications, manufacturing process and technology, functions and uses, pricing, distribution and marketing, and tariff classification; they are technically and commercially substitutable. The issue of like article was also examined by the Authority in the original investigation. Accordingly, for the purpose of the present sunset review, the product produced by the

domestic industry is treated as 'like article' to the product under consideration produced in and imported from the subject countries.

D. Domestic industry & standing

9. The application has been filed by Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited, which is the sole producer of the subject goods in India. The applicant has certified that it has not imported the subject goods from the subject countries and that it is not related to any producer or exporter of the subject goods in the subject countries or to any importer of the subject goods in India. Based on information available on record, the Authority is satisfied that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and that the application has been made 'by or on behalf of the domestic industry'. The application also satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3), even though the requirements of Rule 5(3) are not applicable to a sunset review investigation.

E. Subject countries

10. The subject countries in the present investigation are China PR, Japan and Korea RP, which are the same as the subject countries in the original investigation and the first sunset review investigation.

F. Period of investigation

11. The period of investigation for the present investigation is 1st April 2025 to 31st March 2026 (12 months). The injury examination period covers 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025 and the period of investigation.

G. Basis of alleged dumping

i. Normal value for China PR

12. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that the Chinese producers should be called upon to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods, in terms of Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The applicant has submitted that it could not obtain reliable information on the price or constructed value in an appropriate market economy third country. It has further submitted that the price from a market economy third country to other countries, including India, cannot be adopted, since imports from the European Union and Saudi Arabia have been found by the Authority to be at dumped prices in the recently concluded sunset review investigation concerning those countries. The applicant has, therefore, determined the normal value for China PR on the basis of the price actually paid or payable in India for the like product, considering the cost of production in India duly adjusted for selling, general and administrative expenses and a reasonable profit, in terms of Para 7 of Annexure-I to the Rules. For the purpose of initiation, China PR has been treated as a non-market economy, subject to rebuttal by the producers and exporters concerned in accordance with Para 8 of Annexure-I to the Rules, and the normal value has been constructed in terms of Para 7 of Annexure-I to the Rules.

ii. Normal value for Japan and Korea RP

13. The Authority notes that Section 9A(1)(c) of the Act specifies the comparable price in the ordinary course of trade for the like article when meant for consumption in the exporting country and, where such price is not available, a comparable representative price of the like article when exported from the exporting country to an appropriate third country or the cost of production in the country of origin with reasonable additions for administrative, selling and general costs and for profits. The applicant has submitted that it was unable to obtain information regarding the domestic selling prices of the subject goods in Japan and Korea RP. Accordingly, the applicant has relied upon price information published on the ChemAnalyst website for the purpose of determining the normal value.

The said website reports prices of the subject goods prevailing in the Asia-Pacific region. The applicant has also supplemented the said information by furnishing an estimate of the cost of production of the subject goods in the respective countries of origin.

14. The Authority notes that ChemAnalyst price information provided by the applicant covers only one quarter of the period of investigation and does not clarify whether such prices are in-country consumption prices. As regards the estimated cost of production, the applicant has not provided verifiable international raw material or utility prices at this stage. As regards a comparable representative price of the like article when exported to an appropriate third country, the published source available for that purpose reports the trade at the six-digit level which does not cover the subject goods alone. Accordingly, none of these has been considered for the determination of the normal value at this stage. For the purpose of initiation, the normal value in respect of Japan and Korea RP has been determined on the facts available, the optimised cost of production of the like article in India having been adopted as the best information available, duly adjusted and with the addition of a reasonable profit margin. Subsequent to initiation, the normal value shall be determined on the basis of the responses of the producers and exporters concerned and such further evidence as may be placed on record.

iii. Export price

15. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG Systems transaction wise import data. Appropriate adjustments, as claimed by the applicant, have been considered on account of ocean freight, marine insurance, port expenses, inventory carrying cost and credit cost to arrive at the ex-factory export price.

iv. Dumping margin

16. Based on the normal value and the export price determined as stated above, the dumping margin is *prima facie* positive and significant for each of the subject countries, indicating *prima facie* that dumping of the subject goods from the subject countries has continued.

H. Likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury

17. The applicant has provided *prima facie* evidence of continued injury to the domestic industry. The volume of imports from the subject countries has increased in absolute terms and in relation to production and consumption in India. The price undercutting from the subject countries is positive, the dumped imports have *prima facie* depressed the prices of the applicant, which sold below its cost of sales throughout the injury period, and the landed value of the subject imports is below the non-injurious price of the domestic industry. The applicant has operated below optimum capacity utilisation, its market share has declined over the injury period, and it has suffered financial losses, cash losses and negative return on capital employed throughout the injury period. The applicant has further claimed that there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of the anti-dumping duty, as the producers in the subject countries hold significant production capacities, which are several times the demand in India, and further capacity expansions are being undertaken in China PR. It has also claimed that the producers in the subject countries are export oriented, and that a significant share of the exports from the subject countries to third countries is at prices below the estimated normal value and the non-injurious price of the domestic industry, and below the export price to India. The information furnished by the applicant *prima facie* shows continuation of dumping from the subject countries and the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duty.

I. Initiation of sunset review investigation

18. On the basis of the duly substantiated written application filed by the applicant, and having satisfied itself on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant substantiating the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the anti-dumping duty in force in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries, and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

J. Procedure

19. The sunset review investigation will cover all aspects of the final findings No. 14/36/2016-DGAD dated 13th December 2017 recommending the imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries and the final finding No. 7/26/2021-DGTR dated 27th August 2021 recommended continued imposition of anti-dumping duty.
20. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules shall be applicable *mutatis mutandis* in this review.

K. Submission of information

21. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<http://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding Setu case ID - AD/SSR/011/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
22. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their Embassies in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits set out below. All such information must be filed in the form and manner prescribed by this initiation notification, the Rules and the applicable trade notices issued by the Authority.
23. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner, and within the time limits, set out in this notification, the Rules and the applicable trade notices issued by the Authority. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
24. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (<http://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of the DGTR (<http://dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications and other such information.

L. Time limit

25. Any information relating to the present investigation must be uploaded by the interested parties on the SETU portal (<http://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding Setu case ID - AD/SSR/011/2026. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV), must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject countries, in accordance with Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
27. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in paragraph 25 of this initiation notification.
28. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. The extension of 15 days shall be granted from the date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15 days extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with Rule 6(4) of the Rules.
29. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

M. Submission of information on confidential basis

30. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
31. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto) before the Authority, including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
32. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
33. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information

which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

34. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
35. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
36. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
37. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
38. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
39. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

N. Inspection of public file

40. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU Portal.

O. Non-cooperation

41. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority